भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3984
मंगलवार, 25 मार्च, 2025/04चैत्र, 1947 (शक) को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस

3984. श्री अरविंद गणपत सावंतः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सहकारी समितियों के लिए राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस तैयार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो सहकारी डाटाबेस तैयार करने में शामिल बिंदुओं/मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;
(ग) सहकारी क्षेत्र में डाटाबेस तैयार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इसके उद्देश्य क्या हैं;
(घ) उपर्युक्त डाटाबेस नीति निर्माताओं और सहकारी क्षेत्र के अन्य हितधारकों के लिए किस प्रकार सहायक होगा;
(ङ) क्या राज्य सरकार और अन्य हितधारक उक्त डाटाबेस का उपयोग करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) उक्त डाटाबेस को किस प्रकार सुरक्षित किया जाएगा और वास्तविक समय के आधार पर अद्यतन किया जाएगा; और
(छ) उक्त डाटाबेस तैयार किए जाने के बाद सहकारी समितियों को होने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख): जी हां, मान्यवर । सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहयोग से एक व्यापक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) का विकास किया गया है । NCD पोर्टल को दिनांक 08 मार्च, 2024 को लॉन्च किया गया था । यह डेटाबेस देश की 8.30 लाख सहकारी समितियों की सूचना का सिंगल पॉइंट एक्सेस प्रदान करता है । राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस में आवश्यकतानुसार सुधार किये जाते हैं और कार्यात्मकता के साथ नए डेटा सेट्स जोड़े जाते हैं जो कि एक अनवरत प्रक्रिया होती है ।

(ग) राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) का लक्ष्य देश भर की सहकारी समितियों की सूचना का एक व्यापक संकलन का निर्माण करना है । राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस को तीन चरणों में विकसित किया गया है । चरण- । में जो फरवरी, 2023 में पूरा हुआ, में जिला पंजीयक कार्यालयों और AICTE के 500 स्थानीय इंटर्नों की सहायता से कृषि, डेयरी और मात्स्यिकी में लगभग 2.64 लाख प्राथमिक सहकारी समितियों का मानचित्रण किया गया । चरण-II में विभिन्न सहकारी बैंकों और परिसंघों से आंकड़े एकत्र करके राष्ट्रीय सहकारी समितियों/परिसंघों और उनके जिला एवं राज्य स्तर के लिंकेजों का मानचित्रण किया गया । मई, 2023 में शुरू किए गए चरण-III में इस डेटाबेस को अन्य सेक्टरों के 5.3 लाख से भी अधिक सहकारी समितियों तक विस्तारित किया गया जिसमें लगभग सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा सहकारी समितियों के संबंधित पंजीयक कार्यालयों के माध्यम से डाटा प्रविष्टियां पूरी की गईं ।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस https://cooperatives.gov.in पर सुलभ उपलब्ध है । सहकारी आंदोलन को विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां समितियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, में सशक्त करने के लिए नीति निर्माताओं, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों द्वारा इस डेटाबेस का उपयोग किया जा सकता है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस सहकारी समितियों की अवस्थिति, सदस्यता, आर्थिक कार्यकलाप, अवसंरचना, आच्छादित और अनाच्छादित ग्राम पंचायतों सहित सहकारी समितियों के भौगोलिक प्रसार की कमियों की पहचना में सहायक वित्तीय प्रदर्शन एवं संपरीक्षण विवरणों जैसे मानदंडों पर आंकड़े संकलित करता है ।

(च) डाटा निजता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) पोर्टल राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अवसंरचनाओं का अनुपालन करता है और एक संरक्षित, मापनीय एवं विश्वस्त क्लाउड आधारित अवसंरचना में होस्ट किया जाता है । सरकार द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के अधीन कठोर डाटा सुरक्षा नीतियां लागू की जा रही हैं । इस डेटाबेस में सहकारी समितियों की डाटा का एकत्रण, प्रविष्टि और अद्यतन सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त नोडल अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है ।

(छ) राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) सहकारी समितियों के बीच वर्टिकल और हॉरिजोंटल लिंकेजों की अंतरदृष्टि प्रदान करता है और सहकारी परितंत्र में इन संस्थाओं के बीच परस्पर संबंधों के बारे में बहुमूल्य सूचना प्रदान करता है । यह डेटाबेस एक बहुमुखी और शक्तिशाली उपकरण है जो हितधारकों को बहुमूल्य सूचना और विश्लेषणात्मक क्षमता से समर्थ करता है जिसके परिणामस्वरूप सहकारी समितियों की समग्र कार्यात्मकता और शासन में वृद्धि होती है ।

*****